

## अमेरिका-चीन तनाव के नए आयाम

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में अमेरिका और चीन के मध्य हितों के टकराव के मुद्दों पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

### संदर्भ

अमेरिका और चीन के मध्य लंबे समय से चल रहा व्यापार युद्ध अपने अंतमि चरण में दखिला दे रहा है। वगित कुछ महीनों से दोनों देश व्यापार समझौते को अंतमि रूप देने का अथक प्रयास कर रहे हैं, इस क्रम में पहला सुव्यवस्थित प्रयास तब दखिला दिया जब अमेरिका ने चीन के 160 अरब डॉलर के सामानों पर शुल्क लगाने के विरोध को कुछ समय के लिये टाल दिया। हालाँकि ऐसी समय में दोनों देशों के मध्य प्रतिविवरित व्यापार से कहीं आगे बढ़ चुकी है। अब आर्थिक मुद्दों से इतर हॉन्गकॉन्ग की स्वायत्तता, उड़गर मानवाधिकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल स्पेस और 5G जैसे मुद्दे विविध की नवीन पृष्ठभूमियां गए हैं। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि विश्व की दो बड़ी शक्तियों के मध्य संघर्ष का विश्व के विभिन्न देशों पर कसि प्रकार का प्रभाव होगा और विशेष तौर पर भारत के लिये इसके क्या मायने हैं?

### ऊर्जा संबंधी चति

- हाल के कुछ वर्षों में अमेरिका ने अपनी ऊर्जा संबंधी आयात नियंत्रित को काफी कम किया है जिससे वैश्विक बाजार में मांग में कमी आने के कारण तेल की कीमतें काफी कम हो गई थीं, जो कि भारत के लिये एक संतोषजनक खबर थी क्योंकि भारत कच्चे तेल की अपनी 80 प्रतशित से अधिक और प्राकृतिक गैस की 40 प्रतशित ज़रूरतों को पूरा करने के लिये आयात पर नियंत्रित रहता है।
  - वैश्विक बाजार में तेल की कम कीमतें भारत को अपने चालू खाते घाटे को संबोधित करने में मदद कर सकती थीं।
- किंतु ईरान की कुदस फोरस के प्रमुख और ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारी मेजर जनरल कासमि सुलेमानी की मृत्यु के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में अचानक 4 प्रतशित की बढ़ोतारी देखी गई है।
- भारत के विपरीत चीन ईरान से काफी अधिक मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है और ईरान का सबसे बड़ा खरीदार भी है। हाल ही में चीन ने घोषणा की थी कि वह ईरान के तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों को विशिष्टित करने में 280 बिलियन डॉलर का निवाश करेगा।
- मध्य-पूर्व में हुए हालिया घटनाक्रम को लेकर भी चीन ने अपना पक्ष रखते हुए अमेरिका से संयम बरतने एवं तनाव को और अधिक न बढ़ाने का आग्रह किया है। इस विषय पर चीन के पक्ष से स्पष्ट है कि वह स्वयं को 'ईरान से सहानुभूति रखने वाले' के रूप में प्रदर्शित करना चाहता है। ऐसे में चीन की यह नीति अमेरिका और चीन के मध्य प्रतिविवरित एवं तनाव को और अधिक बढ़ा देगी।
- अनुमानतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में अमेरिका से भारत का ऊर्जा आयात 10 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। जहाँ ऊर्जा आयात के लिये अमेरिका पर भारत की नियंत्रित बढ़ रही है, वहीं चीन मध्य-पूर्व में अपनी उपस्थितियों और अधिक मजबूत कर रहा है।
- यह कहा जा सकता है कि विभिन्न में ऊर्जा क्षेत्र दोनों के मध्य प्रतिविवरित के लिये एक नई भूमितैयार करेगा।

### तकनीक के क्षेत्र में

- स्पष्ट है कि भविष्य में जिस देश के पास सर्वाधिक उन्नत तकनीक होगी वही वैश्विक पटल पर एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। यही कारण है कि विश्व की दो बड़ी शक्तियाँ (अमेरिका और चीन) तकनीक के क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिये भरसक प्रयास कर रही हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों पर चीन के महत्वाकांक्षी द्वितीय देश ने अमेरिकी प्रशासन के समक्ष एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है।
- वर्ष 2019 की शुरुआत में अमेरिका ने चीन की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे (Huawei) पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी इंटेलज़िंस विभाग का मानना था कि हुआवे द्वारा तैयार किये जा रहे उपकरण देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त दिसंबर 2018 में अमेरिकी अधिकारियों के कहने पर हुआवे के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) मेंग वानझो को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया था।
- दोनों देशों के मध्य चल रहे तकनीक युद्ध (Tech War) में अब तक भारत इसे अपने अनुकूल नहीं बना पाया है। ऑफिर्डों पर गौर करें तो वर्ष 2018 में चीन की तीन बड़ी टेक कंपनियों-बाईडू, अलीबाबा और टेंसेंट ने भारत के स्टार्ट-अप्स में तकरीबन 5 बिलियन डॉलर का निवाश किया था।

- भारत इस अवसर का उपयोग कर चीन को भारत के IT नरियातों के लिये अपना बाजार खोलने हेतु मजबूर कर सकता था, किंतु अब तक ऐसा संभव नहीं हो पाया।
- अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तकनीक युद्ध से भारत की सामरकि स्वायत्तता को भी खतरा है। वर्दित हो कि हाल ही में भारत ने अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित कंपनी हुआवे को देश में 5G ट्रायल के आयोजन में हसिसा लेने की अनुमति दी है।

## हॉन्गकॉन्ग की स्वायत्तता और उझार समुदाय के मानवाधिकार का मुद्दा

- वर्ष वर्ष हॉन्गकॉन्ग में लोकतंत्र के समरथकों के प्रतिएकजुट्टा दिखाते हुए अमेरिका ने हॉन्गकॉन्ग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत अमेरिकी प्रशासन को इस बात का आकलन करने की शक्ति दी गई है कि हॉन्गकॉन्ग में अशांतिकी वजह से इसे वशीष क्षेत्र का दर्जा दिया जाना उचित है या नहीं।
- चीन की सरकार ने हॉन्गकॉन्ग को उसका आंतरिक विषय बताते हुए अमेरिका के इस अधिनियम को चीन की संपर्भुता पर खतरा माना था।
- इसके अलावा हाल ही में अमेरिका के नियों सदन ने चीन के उझार मुसलमानों के संबंध में भी एक विधियक पारित किया था। हालाँकि यह विधियक अभी ऊपरी सदन सीनेट (Senate) द्वारा पारित होना बाकी है।
  - अधिनियम बनने के पश्चात् इसके माध्यम से अमेरिका द्वारा चीन पर उसके शनिजियांग (Shinxiang) प्रांत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ किये जाने वाले दुरव्यवहार के कारण कई प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे। इनमें वरषित चीनी अधिकारियों तथा चीन को होने वाले नरियात पर प्रतिबंध भी शामिल है।
  - ज्ञात हो कि अमेरिका के इस कदम के प्रत्युत्तर में चीन ने अमेरिकी सेना के जहाजों तथा एयरक्राफ्ट को हॉन्गकॉन्ग में जाने से मना कर दिया था।

## व्यापार युद्ध और भारत

- जब एक देश दूसरे देश के प्रतिसिरक्षणवादी रवैया अपनाता है अर्थात् वहाँ से आयात होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क बढ़ाता है तो दूसरा देश भी जवाबी कार्रवाई में यही प्रकरणीय अपनाता है। ऐसी संरक्षणवादी नीतियों के प्रभाव को व्यापार युद्ध (Trade War) कहते हैं।
- अमेरिका और चीन बीते लगभग 17 महीनों से व्यापार युद्ध में उलझे हुए हैं। विशेषकों को उम्मीद थी कि इस व्यापार युद्ध से भारत को काफी लाभ होगा, परंतु स्टेट ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा जारी जुलाई 2019 की एक रपोर्ट बताती है कि अमेरिका-चीन के व्यापार युद्ध से भारत को काफी कम लाभ हुआ है।
- ऑक्डों के मुताबिकि, वर्ष 2019 की पहली छमाही में व्यापार युद्ध के कारण अमेरिकी बाजार में चीन के नरियात में लगभग 35 बिलियन डॉलर की कमी आई थी। इसमें से लगभग 14 बिलियन डॉलर की आपूर्ति अमेरिकी उत्पादकों द्वारा की गई, जबकि शेष 62 प्रतिशत यानी 21 बिलियन डॉलर की आपूर्ति अन्य देशों द्वारा की गई। अन्य देशों द्वारा की गई आपूर्ति में भारत का हसिसा मात्र 755 मिलियन डॉलर था, जो किसी भी रूप से दर्शाता है कि भारत इस अवसर का फायदा प्राप्त नहीं कर सकता था।

**प्रश्न:** अमेरिका-चीन तनाव की वृद्धि में नए क्षेत्रों की भूमिका का उल्लेख करते हुए वैश्वकि अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिये।